भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 135

जिसका उत्तर 07 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है।

16 अग्रहायण, 1944 (शक)

आईटी योजनाओं को बढ़ावा देना

135. श्री नकुल के. नाथ:
श्री सुनील कुमार मंडल:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा 2014 के बाद से अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए शुरू और कार्यान्वित किए गए कार्यक्रम/योजनाओं की संख्या का पश्चिम बंगाल सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन कार्यक्रमों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो अभी भी विद्यमान है/नाम बदल गया है तथा इस संबंध में भावी पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 2014 के बाद से अब तक इन योजनाओं के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख): भारत सरकार का लक्ष्य अपनी आत्मनिर्भर भारत आर्थिक नीतियों के हिस्से के रूप में भारत को एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण केंद्र बनाना है। इस संबंध में, सरकार ने हमारे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम को व्यापक और गहन बनाने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाये हैं और पहल की हैं। अखिल भारतीय योजनाओं का विवरण **अनुबंध- I** में प्रदान किया गया है और राज्य-वार योजनाओं का विवरण **अनुबंध- II** में प्रदान किया गया है।

(ग): वर्ष **2014** के बाद अब तक इन योजनाओं के लिए बजट **आबंटन:**

करोड़ रु. में

योजनाएं/कार्यक्रम	**बजट अनुमान (2014 के बाद से अब तक)**	**संशोधित अनुमान (2014 के बाद से अब तक)**
ईएमसी 2.0	3762.25	3762.25
एसपीईसीएस	2386	2386
एलएसईएम के लिए पीएलआई	40,995	40,995

योजना		
आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना	7350	7350
भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब इकोसिस्टम का विकास	0.00	200.00

अनुबंध -I

2014 के बाद से अब तक इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू और कार्यान्वित कार्यक्रम /योजनाएं

1. राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिकी नीति 2019 : राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिकी नीति 2019 (एनपीई 2019) को 25.02.2019 को अधिसूचित किया गया है। एनपीई 2019 का विजन भारत को ईएसडीएम के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है , जो चिपसेट सहित प्रमुख घटकों को विकसित करने के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्सा हित कर रहा है, और उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सक्षम वातावरण बना रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने और प्रोत्साहित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एनपीई 2019 के तत् वावधान में निम्नलिखित ती न योजनाओं को अधिसूचित किया गया है:

i. दिनांक 01.04.2020 की राजपत्र अधिसूचना सं .सीजी -डीएल -ई -01042020-218990 द्वारा अधिसूचित बड़े पैमाने पर **इलेक्ट्रोनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)** मोबाइल फोन विनिर्माण और असेंबली , टेस्टिंग , मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) सहित निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के वि निर्माण में शामिल पात्र कंपनियों को वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष से अधिक) पर 4% से 6% का प्रोत्साहन प्रदान करती है।

अगले 5 वर्षों में , 16 स्वीकृत कंपनियों से 1**0,50,000 करोड़ रुपये** (10.5 लाख करोड़ रुपये) से अधिक **का कुल उत्पादन होने** की उम्मीद है। अगले 5 वर्षों में 10,50,000 करोड़ रुपये के कुल उत्पादन में से , 6,50,000 करोड़ रुपये की **पूर्ति लगभग 60% के निर्यात द्वारा होने की उम्मीद** है । इस योजना के तहत स्वीकृत कंपनियों से उम्मीद है कि ये 11,000 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रोनिकी विनिर्माण में **अतिरिक्त निवेश** ला एंगी और **2 लाख प्रत्यक्ष रोजगार** सृजित करेंगी ।

मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण में निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना के पहले दौर की सफलता के बाद , निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रोत्साह न देने के लिए बड़े **पैमाने पर इलेक्ट्रोनिकी विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना का दूसरा** दौर 11.03.2021 को शुरू किया गया था । दूसरे दौर के तहत , पात्र कंपनियों को चार (4) वर्षों की अवधि के लिए , भारत में निर्मित और लक्ष्य खंड के तहत कवर किए गए सामानों की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष यानी 2019-20 से अधिक) पर 5% से 3% की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

अगले 4 वर्षों में , अनुमोदित 16 इलेक्ट्रॉनिक घटक **विनिर्माताओं से 12,432 करोड़ रुपये तक का कुल उत्पादन** होने की उम्मीद है । योजना के दूसरे दौर से इलेक्ट्रोनिकी विनिर्माण में **573 करोड़ रुपये** का **अतिरिक्त निवेश** आने की उम्मीद है ।

ii.**आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई)** जिसे 03.03.2021 को अधिसूचित किया गया था। यह योजना लक्ष्य सेगमेंट - लैपटॉप , टैबलेट , ऑलइन -वन पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) और सर्वर के तहत माल की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर 4% से 2% / 1% का प्रोत्साहन देती है। कुल अनुमोदित योजना परिव्यय रु 7,350 करोड़ है और 14 कंपनियां (श्रेणियाँ : आईटी हार्डवेयर कंपनियां - 4,

घरेलू कंपनियां - 10) और कुछ प्रमुख वैश्विक ब्रांड ईएमएस और ओईएम सहित पीएलआई योजना के तहत अनुमोदित की गई हैं।

iii. दिनांक 01 अप्रैल, 2020 की राजपत्रित अधिसूचना द्वारा अधिसूचित **इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालकों (स्पेक) के विनिर्माण** को बढ़ावा देने की योजना इलेक्ट्रॉनिक सामानों की पहचान सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की डाउनस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला शामिल है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक घटकों, अर्धचालक/प्रदर्शन निर्माण इकाइयों, एटीएमपी इकाइयों, विशेष उप-विधान सभाओं और उपरोक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए पूंजीगत सामान। यह योजना 31.03.2023 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली है।

11,130 करोड़ रुपये के **कुल परियोजना परिव्यय** और 1,519 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध प्रोत्साहन के साथ 30.11.2022 तक बत्तीस (32) आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत **आवेदनों की कुल रोजगार सृजन** क्षमता 32,457 है।

iv . 01 अप्रैल, 2020 की राजपत्र अधिसूचना सं.सीजी-डीएल-ई-01042020-218991 द्वारा अधिसूचित संशोधित **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0)** योजना देश में इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को उनकी आपूर्ति श्रृंखला के साथ-साथ आकर्षित करने के लिए रेडी बिल्ट फैक्ट्री (आरबीएफ) शेड/प्लग एंड प्ले सुविधाएं सहित सामान्य सुविधाओं और प्रसुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करती है। यह योजना देश भर में ईएमसी परियोजनाओं और सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) दोनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आवेदन की प्राप्ति के लिए 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि सहित इसकी अधिसूचना की तारीख से 8 वर्ष की अवधि के लिए योजना का बजटीय परिव्यय 3,762.25 करोड़ रुपये है।

v. इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कोष (ईडीएफ):

दिनांक 06 जनवरी , 2015 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 8(9)/2011-आईपीएचडब्ल्यू द्वारा अधिस ूचित इलेक्ट्रोनिकी विकास निधि (ईडीएफ), पेशेवर रूप से प्रबंधित "डॉटर फंड" में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रोनिकी विकास निधि (ईडीएफ) को "फंड ऑफ फंड्स" के रूप में स्थापित किया गया है जो बदले में इलेक्ट्रोनिकी , नैनो-इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में नई तकनीकों को विकसित करने वाली कंपनियों को जोखिम पूंजी प्रदान करता है। इस कोष से इन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ईडीएफ इन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बाजार संचालित अनुसंधान और विकास करने के लिए उद्योग को जोखिम पूंजी प्रदान करने के लिए एक इकोसिस्टमके निर्माण में सक्षम बनाता है। इस प्रक्रिया में, यह देश में बौद्धिक संपदा को समृद्ध करेगा और अधिक उद्यमियों को उत्पाद और प्रौद्योगिकी विकास के लिए प्रोत्साहित करेगा। ईडीएफ में अपने योगदानकर्ताओं के 216.33 करोड़ रुपये शामिल हैं जिसमें एमईआईटीवाई के 210.33 करोड़ रूपए हैं । ईडीएफ द्वारा 8 डॉटर फंडों में निवेश करने की उम्मीद है और ईडीएफ द्वारा इन 8 डॉटर फंडों के लिए प्रतिबद्ध राशि 271.30 करोड़ रुपये थी।

2. भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम :

आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और भारत को ईएसडीएम के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए , मंत्रिमंडल ने ₹ 76,000 करोड़ (>10 बिलियन अमरी की डालर) के परिव्यय के साथ देश में एक स्थायी अर्धचालक और प्रदर्शन इकोसिस्टम के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम को मंजूरी दी। यह कार्यक्रम सेमीकंड क्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के साथ -साथ डिजाइन में कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करके इलेक्ट्रोनिकी निर्माण में एक नए युग की शुरूआत करेगा। यह रणनीतिक महत्व और आर्थिक आत्मनिर्भरता के इन क्षेत्रों में भारत के तकनीकी नेतृत्व का मार्ग प्रशस्त करेगा। उपरोक्त कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित चार योजनाएं शुरू की गई हैं:

i) इलेक्ट्रोनिकी विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने और एक विश्वसनीय मूल्य श्रृंखला स्थापित करने में मदद करने के लिए देश में सेमीकंडक्टर **वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना** के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए **'भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना'** । यह योजना भारत में सिलिकॉन सीएमओएस आधारित सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए समान आधार पर परियोजना लागत के 50% के वित्तीय समर्थन देती है ।

ii) इलेक्ट्रोनिकी विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश में टीएफटी एलसीडी या एमोलेड आधारित डिस्प्ले पैनल के विनिर्माण के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए '**भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना** ' । यह योजना भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

iii) **'कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग (एटी एम् पी)/ओ एस ए टी सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना'** भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स (एस आई पी एच)/सेंसर (एम् ई एम् एस सहित) फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर एटी एम् पी / ओ एस ए टी सुविधाओं की स्थापना के लिए समान आधार पर पूंजीगत व्यय के 50% का वित्तीय समर्थन प्रदान करेगी ।

iv) **'डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना'** एकीकृत सर्किट (आईसी), चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स (एसओसी), सिस्टम और आईपी कोर और सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिजाइन के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन के विकास और परिनियोजन के विभिन्न चरणों में वित्तीय प्रोत्साहन, डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता प्रदान करती है। यह योजना प्रति आवेदन रु 30 करोड़ की सीमा के अधीन 5 वर्षों में शुद्ध बिक्री कारोबार के 6% से 4% के "नियोजन संबद्ध प्रोत्साहन" और प्रति आवेदन रु 15 करोड़ की सीमा के बशर्ते पात्र व्यय के 50% तक का "उत्पाद डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन" प्रदान करती है ।

पश्चिम बंगाल में एमईआईटीवाई द्वारा किए गए विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का विवरण:

1. **प्रौद्योगिकी ऊष्मायन और उद्यमियों का विकास (टाइड 2.0 योजना):** सामाजिक प्रासंगिकता के सात पूर्व -पहचाने क्षेत्रों में आईओटी, एआई, ब्लॉक -चेन , रोबोटिक्स आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में प्राथमिक रूप से लगे आईसीटी स्टार्टअप का समर्थन करने में इनक्यूबेटरों को वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एमईआईटीवाई ने वर्ष 2019 में इस योजना की शुरुआत की है । इस योजना को 51 इनक्यूबेटरों के माध्यम से तीन स्तरीय संरचना के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है , जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों और प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठनों में ऊष्मायन गतिविधियों को बढ़ावा देना है , जिसके परिणामस्वरूप अंततः पांच वर्षों की अवधि में लगभग 2000 तकनीकी स्टार्ट -अप की सहायता की जा सकती है। 5 वर्षों की अवधि

में इस योजना का कुल परिव्यय 264.62 करोड़ रुपये है। टाइड 2.0 योजना के तहत समर्थित इन्क्यूबेशन केंद्रों की राज्य -वार सूची अनुबंध -I के रूप में संलग्न है।

टाइड 2.0 योजना के तहत, 1 इन्क्यूबेशन सेंटर जिसका नाम "आईआईएम कलकत्ता इनोवेशन पार्क" है पश्चिम बंगाल राज्य में टाइड 2.0 केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है:

2. **टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ़ एंटरप्रेन्योर्स (टाइड) योजना :** सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स (आईसीटीई) डोमेन में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2008 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा प्रौद्योगिकी ऊष्मायन और उद्यमियों का विकास (टीआईडीई) योजना शुरू की गई थी। TIDE योजना के तहत, युवा उद्यमियों को उनके द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायिक दोहन के लिए प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनियों को बनाने में सक्षम बनाने के लिए उनके प्रौद्योगिकी ऊष्मायन केंद्रों को मजबूत करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।15 टाइड केंद्रों को समर्थन देने के लिए 23.40 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ योजना शुरू की गई थी , वर्ष 2009 में 25.934 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय के साथ अतिरिक्त 12 टाइड केंद्रों को शामिल करने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया था। इस योजना के तहत , पूरे भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में 27 टाइड केंद्रों और 2 वर्चुअल टाइड केंद्रों को सहायता दी गई है। टाइड 1.0 योजना को औपचारिक रूप से 31.03.2020 को बंद कर दिया गया।

वर्तमान स्थिति के अनुसार टाइड 1.0 योजना 31.03.2020 को समाप्त हो गई थी। पश्चिम बंगाल राज्य में, "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर" नामक एक टाइड केंद्र संचालित किया गया था।

आंध्र प्रदेश में एमईआईटीवाई द्वारा किए गए विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का विवरण:

आरआईएनएल विशाखापत्तनम में उद्योग पर उद्यमिता केंद्र 4.0:

बढ़ते औद्योगिक स्वचालन की पृष्ठभूमि में उद्योग 4.0 उत्पादों और समाधानों की मांग तेजी से बढ़ने वाली है। उद्योग 4.0 उत्पादों और समाधानों की घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने से घरेलू उद्योग उत्पादों, पेटेंट और आईपीआर में वृद्धि के माध्यम से मूल्य-श्रृंखला में उल्लेखनीय रूप से ऊपर जाएगा। इन क्षेत्रों में

स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र 4.0 (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, संवर्धित वास्तविकता, आभासी वास्तविकता, औद्योगिक स्वचालन, औद्योगिक रोबोटिक्स, औद्योगिक ड्रोन, औद्योगिक आईओटी, औद्योगिक 3 डी प्रिंटिंग और एआई द्वारा संचालित अन्य संबंधित प्रौद्योगिकियां) आरआईएनएल विशाखापत्तनम में स्थापित किया जा रहा है । इस सीओई की योजना 5 वर्षों की अवधि में 175 स्टार्टअप्स को पोषित करने की है। परियोजना को 14.10.2021 को मंजूरी दी गई थी। परियोजना का कुल परिव्यय 20.32 करोड़ रुपये है (एमईआईटीवाई योगदान- 8.32 करोड़ रुपये)

तमिलनाडु में एमईआईटीवाई द्वारा किए गए विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का विवरण:

चेन्नई में iतमिलनाडु प्रौद्योगिकी (iTNT) हब

एनपीएसपी के तहत एक सॉफ्टवेयर उत्पाद क्लस्टर स्थापित करने के लिए, चेन्नई में iTamil Nadu Technology (iTNT) हब नामक पहला क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। तमिलनाडु टेक्नोलॉजी हब का प्राथमिक उद्देश्य तमिलनाडु में डीप टेक इनोवेशन इकोसिस्टम का पोषण करना होगा जो विशेष रूप से डीप टेक में स्केलिंग अप चरण में स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन, विकास, कार्यान्वयन और समर्थन कर सकता है। आईटीएनटी हब पांच साल की अवधि में डीप टेक/उभरती तकनीक में 200 स्टार्ट-अप/प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी लाने में मदद करेगा। इसके अलावा पांच साल की अवधि में 200 स्टार्ट-अप को हब एंड स्पोक मॉडल में समर्थन दिया जाएगा और त्वरण और ढांचागत सेवा प्रदान की जाएगी। परियोजना को 03.03.2022 को 5 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी, परियोजना का कुल परिव्यय 54.61 करोड़ (एमईआईटीवाई योगदान 27 करोड़) है।

बीपीओ योजनाएं:

रोजगार के अवसर सृजित करने और आईटी/आईटीईएस उद्योग का छोटे शहरों और कस्बों में प्रसार करने के लिए, सरकार ने वर्ष 2015 और 2016 में क्रमशः 50 करोड़ और 493 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत दो बीपीओ प्रोत्साहन योजनाएँ, अर्थात् नॉर्थ ईस्ट बीपीओ प्रमोशन स्कीम (एनईबीपीएस) और इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम (आईबीपीएस) शुरू की थीं। इन योजनाओं का लक्ष्य व्यवहार्यता गैप निधियन के रूप में प्रति सीट रु 1 लाख तक 50% वित्तीय सहायता प्रदान करके बीपीओ/आईटीईएस संचालन की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। नई बोलियों को आमंत्रित करने के लिए आईबीपीएस और एनईबीपीएस की अवधि क्रमशः 31.03.2019 और 31.03.2020 तक थी, हालांकि वित्तीय सहायता का संवितरण योजना की समय-सीमा के अनुसार इस अवधि से अधिक हो सकता है। इन योजनाओं की स्थापना के बाद से, 246 इकाइयों ने देश के 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बीपीओ/आईटीईएस संचालन स्थापित किए हैं, जो 51,492 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें से 6 इकाइयां पश्चिम बंगाल में स्थापित हैं, जो 274 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती हैं।

****

अनुबंध- II

51 टाइड 2.0 इन्क्यूबेशन केंद्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्यों का नाम	इन्क्यूबेशन केंद्र का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	1) आंध्र प्रदेश इनोवेशन सोसाइटी, चित्तूर 2) सेंटर फॉर इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईई), केएल यूनिवर्सिटी, गुंटूर 3) ग्रामीण इन्क्यूबेशन सेंटर , विशाखापत्तनम 4) आईआईएम विशाखापत्तनम इन्क्यूबेशन सेंटर , विशाखापत्तनम 5) सीआईई आईआईआईटी हैदराबाद (अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान - हैदराबाद फाउंडेशन) 6) आईआईआईटीएस, श्री सिटी, चित्तूर में नवाचार और उद्यमिता विकास केंद्र 7) अटल इनक्यूबेशन सेंटर – एएलईएपी वी-हब, हैदराबाद (एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया)
2.	असम	डाउन टाउन वेंचर लैब्स, असम डाउन टाउन यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी, असम
3.	बिहार	इंटरप्राइजिंग जोन, पटना
4.	छत्तीसगढ	अटल इंक्यूबेशन सेंटर @36INC सोसायटी, रायपुर
5.	हरियाणा	एमिटी इनोवेशन इनक्यूबेटर, गुरुग्राम
6.	हिमाचल प्रदेश	आईआईटी मंडी कैटालिस्ट, आईआईटी मंडी
7.	गुजरात	1) सेंटर फॉर इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईई), आईआईएम अहमदाबाद 2) इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी (आईक्रिएट), अहमदाबाद 3) गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप और उद्यमिता परिषद (जीयूएसईसी)
8.	कर्नाटक	1) केएलई सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, केएलई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, धारवाड़ **2) नदाथुर एस राघवन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल लर्निंग (एन एस आर सी ई एल), आईआईएम बैंगलोर** 3) सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट (एस आई डी), आई आई एस सी बैंगलोर 4) सी -कैम्प , सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म, बेंगलुरु में बायो इनक्यूबेटर 5) दयानंद सागर एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च एंड बिजनेस इनक्यूबेटर (डी ई आर बी आई) फाउंडेशन, बेंगलुरु 6) आई आई आई टी बी इनोवेशन सेंटर (अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बैंगलोर - इनोवेशन सेंटर
9.	केरल	मेकर विलेज-कोच्चि, आई आई आई टी एम-केरल
10.	मध्य प्रदेश	प्रौद्योगिकी नवाचार और इन्क्यूबेशन सेंटर (टीआईआईसी), अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान (एबीवी-आईआईआईटीएम), ग्वालियर
11.	महाराष्ट्र	1) सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (एस आई एन ई), आई आई टी बॉम्बे 2) संदीप टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टी बी आई), संदीप यूनिवर्सिटी, नासिक 3) एआईसी-पिनेकल एंटरप्रेन्योरशिप फोरम, पुणे
12.	ओडिशा	1) के आई आई टी टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (के आई आई टी -टी बी आई), के आई आई टी, भुवनेश्वर

		2) फाउंडेशन फॉर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इनक्यूबेशन (एफटीबीआई), एनआईटी राउरकेला
13.	पंजाब	साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (टी आई ई टी), पटियाला
14.	राजस्थान	1) पिलानी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सोसाइटी, बिट्स पिलानी 2) अटल इन्क्यूबेशन सेंटर, वनस्थली विद्यापीठ, टोंक 3) आईआईएम उदयपुर इन्क्यूबेशन सेंटर , उदयपुर 4) जेईसीआरसी इन्क्यूबेशन सेंटर (जेईसीआरसी विश्वविद्यालय, जयपुर)
15.	तमिलनाडु	1) फोर्ज एक्सेलेरेटर (कोयम्बटूर इनोवेशन बिजनेस इनक्यूबेटर), कोयम्बटूर 2) पीएसजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरियल पार्क (पीएसजी-एसटीईपी), पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर 3) ओएसिस प्रौद्योगिकी संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली 4) वेल टेक टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर, वेल टेक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवल्लुर 5) आईआईटीएम इन्क्यूबेशन सेल (आईआईटी मद्रास इन्क्यूबेशन सेल) 6) वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (वीआईटीटीबीआई)

16.	तेलंगाना	1) एसआर इनोवेशन एक्सचेंज, वारंगल जेएनटीयू, हैदराबाद से संबद्ध 2) अटल इन्क्यूबेशन सेंटर - सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (इ आई सी -सी सी एम् बी), हैदराबाद 3) आई-टिक फाउंडेशन, आईआईटी हैदराबाद
17.	उत्तराखंड	टाइड बिजनेस इनक्यूबेटर, आईआईटी रुड़की
18.	उत्तर प्रदेश	1) **स्टार्टअप इन्क्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (एस आई आई सी), आई आई टी कानपुर** 2) **एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज, गाजियाबाद** 3) कृष्णा पथ इन्क्यूबेशन सोसाइटी (टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर) के आई ई टी , गाजियाबाद
19.	पश्चिम बंगाल	आईआईएम कलकत्ता इनोवेशन पार्क, कोलकाता
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	दिल्ली (एनसीटी - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	1) **फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (एफ़ आई टी टी), आई आई टी दिल्ली** 2) **दिल्ली इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन सेंटर, आईआईआईटी दिल्ली**
2.	चंडीगढ़	**चितकारा इनोवेशन इनक्यूबेटर फाउंडेशन (सी आई आई एफ़), चितकारा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़**
3.	जम्मू और कश्मीर	**न्यूजेन आईईडीसी बिजनेस इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर**

****